ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN NO.: 2347-2944, RNI : UPBIL04292,REG. No.: 561/2013-2014Vol.-2,No.-2 **PP-416-418**,YEAR-2014

भारतीय कृषि क्षेत्र एवं पशुपालन पर वैश्वीकरण का प्रभाव

☐ डॉ0 इन्द्र प्रताप सिंह

सारांश *– वैश्वीकरण ने दुनिया भर में जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है, विशेषकर विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को। भारत में 1991 के उदारीकरण के बाद यह प्रक्रिया तीव्र हुई, और 2014 तक इसका प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि और पशुपालन जैसे क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखा गया। 2014 को एक निर्णायक काल मानते हुए उस बिंदु तक के वैश्वीकरण के प्रभावों का विश्लेषण किया गया है, जब देश में सत्ता परिवर्तन के साथ नई आर्थिक सोच और कृषि/पशुपालन नीति में भी परिवर्तन की शुरुआत हुई।*

वैश्वीकरण की अवधारणा – वैश्वीकरण का तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति, और तकनीकी को आपस में जोड़ती हैं। इसमें मुक्त व्यापार, सीमा पार पूंजी निवेश, तकनीकी स्थानांतरण और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका शामिल है।

भारत में वैश्वीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – 1991 में भारत ने IMF और World Bank की शर्तों पर उदारीकरण की नीति अपनाई। इसके तहतः विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को प्रोत्साहन, व्यापार बाधाओं को कम करना, सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश, WTO की सदस्यता और TRIPS समझौते में भागीदारी आदि यह प्रक्रिया धीरे–धीरे कृषि और पशुपालन जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में भी प्रवेश करने लगी।

कृषि एवं पशुपालन की पारंपरिक संरचना–

कृषिः मानसून आधारित, देसी बीजों और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित, बहुफसली प्रणाली, आत्मनिर्भर उत्पादन आदि।

पशुपालन देसी नस्लें, ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी, खाद्य सुरक्षा और आजीविका का स्रोत, मिश्रित कृषि प्रणाली का अंग आदि।

सन् 2014, एक राजनीतिक/आर्थिक बदलाव का वर्ष – 2014 में भारतीय राजनीति में बड़ें बदलाव हुए। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार ने आर्थिक विकास, 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' और कृषि सुधारों को प्राथमिकता दी। वैश्वीकरण समर्थक विचारधारा को बल मिला, विशेष रूप से FDI, कृषि–प्रसंस्करण, और डेयरी क्षेत्र में आदि।

कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव –

(क) सकारात्मक प्रभावः विदेशी निवेश से कृषि–प्रसंस्करण इकाइयों का विस्तार, वैश्विक बाजारों तक पहुँच– विशेष रूप से अंगूर, चाय, मसाले, फूल आदि।

फसल विविधीकरणः फूलों की खेती, जड़ी–बूटियाँ, जैविक उत्पाद आदि।

Contract Farming की शुरुआत –

(ख) नकारात्मक प्रभावः देसी बीजों का लोप, हाइब्रिड बीजों की निर्भरता, रासायनिक कृषि और भूमि की उर्वरता में गिरावट, मंडी व्यवस्था का कमजोर होना, WTO के दबाव में सब्सिडी में कटौती, किसान की लागत बढ़ी, आमदनी स्थिर आदि।

(ग) 2014 में विशेष चर्चाः संदक Acquisition Ordinance को लेकर विवाद, कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दरवाज़े खोलने का प्रस्ताव, डिजिटल कृषि (E-NAM जैसी योजनाओं) की भूमिका पर विमर्श आदि।

पशुपालन पर वैश्वीकरण का प्रभाव –(क) **अवसरः** पोल्ट्री और डेयरी में कॉर्पोरेट निवेश, पशु

एसो० प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष– पशुपालन और डेयरी विभाग, श्री मुरली मनोहर टाउन पी० जी० कालेज, बलिया (उ०प्र०) भारत।

टीकाकरण और नस्ल सुधार कार्यक्रम, वैश्विक स्तर पर दुग्ध उत्पादन में भारत की बढ़ती साख आदि।

(ख) चुनौतियाँरू देसी नस्लों की उपेक्षा, आयातित पशु आहार पर निर्भरता, ग्रामीण महिलाओं की भूमिका में कमी, रोगों का प्रसार (बर्ड फ्लू, थ्डव्) वैश्विक बाजार के उतारदृचढ़ाव से स्थानीय व्यापार पर नीतिगत हस्तक्षेप (2014 के बाद के सरकारी कदम) आदि।

(ग) राष्ट्रीय गोकुल मिशन (2014)रू देसी नस्लों को इस योजना के अन्तर्गत संरक्षण दिया गया।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – इन इंडिया के तहत एग्री–बायोटेक सेक्टर में थ्क्, डेयरी प्रसंस्करण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (क्प्क्थ्) आदि इन सबका उद्देश्य वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारतीय कृषि व पशुपालन को खड़ा करना था।

संकट और विरोध – 2013 के बाद किसानों के असंतोष की कई परतें उभरती चली गई जैसे, कर्ज माफी की मांग, फसल बीमा योजनाओं की विफलता, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर असंतोष आदि।

भूमिहीन और महिला किसानों की अनदेखी, भारतीय कृषि व्यवस्था में भूमिहीन एवं महिला किसानों की स्थिति वैश्वीकरण के युग में और भी हाशिए पर चली गई है। भले ही ये वर्ग कृषि उत्पादन और पशुपालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हों, परंतु नीति निर्माण और लाभ वितरण की प्रक्रिया में इनकी उपेक्षा लगातार बनी रही है।

भूमिहीन किसानों की स्थिति – सुधारों की धीमी गतिरू 1990 के दशक के बाद भूमि सुधार कार्यक्रमों की गति ठहर गई, जिससे भूमिहीन किसान औपचारिक रूप से मालिकाना हक से वंचित रह गए।

संविदा खेती (Contract Farming) में भूमिहीनों की कोई भूमिका नहीं बन पाई, क्योंकि कंपनियाँ ज़मीन के मालिक से ही समझौता करती हैं।

मशीनों की बढ़ती भूमिकाः वैश्विक तकनीक आधारित खेती में मानव श्रम की आवश्यकता घटती जा रही है, जिससे भूमिहीन मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं।

वैश्वीकरण समर्थक नीतियों पर विरोध –

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और पंजाब में किसानों ने आंदोलन किए। ये संकेत थे कि वैश्वीकरण से उत्पन्न असंतुलन गहरा रहा है।

सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव – ग्रामीण पलायन में वृद्धि, महिला किसानों की अदृश्यता, जातीय और वर्गीय असमानता में वृद्धि, जल संकट और मृदा प्रदूषण, जैव विविधता में गिरावट आदि है।

सुधार और विकल्प की संभावनाएँ –

(क) **वैकल्पिक दृष्टिकोणः** जैविक खेती, प्राकृतिक कृषि, स्वदेशी बीज बैंक और कृषक समुदाय की भागीदारी, स्थानीय खाद्य तंत्र और मंडी पुनर्गठन, महिला किसान अधिकार नीति आदि है।

(ख) **नीति–सुझावः** WTO की शर्तों पर पुनर्विचार, MSP को वैधानिक दर्जा, Contract Farming में किसानों के अधिकार की सुरक्षा, FDI पर नियमन और पारदर्शिता आदि है।

निष्कर्ष– सन् 2014 तक वैश्वीकरण भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र में गहराई से प्रवेश कर चुका था। यह एक दोधारी तलवार की तरह था कृ एक ओर अवसर, दूसरी ओर गहराते संकट। इसने उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहित किया, किंतु लागत, असमानता, पर्यावरण और सामाजिक ढांचे पर दुष्प्रभाव भी डाले। अतः आवश्यकता है एक संतुलित नीति की, जिसमें भारत के ग्रामीण समाज, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करते हुए वैश्विक तकनीक व पूंजी का उपयोग किया जाए।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. दीक्षित, आर. (2013). भारतीय कृषि का समाजशास्त्र. दिल्लीः राजकमल प्रकाशन।

2. Shiva, Vandana. . Seed Sovereignty, Food Security: Women in the Vanguard. Navdanya.
3. 3. Ministry of Agriculture. (2014). Annual Report 2013–14. भारत सरकार।
4. 4. WTO. . Trade and Agriculture: WTO Documents.
5. 5. FAO. State of Food and Agriculture Report.
6. 6. Dev, S. Mahendra. Agriculture in the Post-Reform Period. IGIDR.
7. 7. NSSO. Situation Assessment Survey of Agricultural Households.
8. 8. National Dairy Development Board. Annual Dairy Statistics.
9. 9. IFPRI. India Agriculture and Nutrition Report.
10. 10. Swaminathan, M.S. (2011). Towards Sustainable Agriculture in the 21st Century.
11. लोकसभा सचिवालय, कृषि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर रिपोर्ट।
12. अखिल भारतीय किसान सभा. वैश्वीकरण और किसान संकट।
13.